

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3572  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

### न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

#### 3572. श्री अभिषेक बनर्जी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विगत दस वर्षों के दौरान न्यायिक व्यवसाय और न्यायपालिका की सेवाओं में रैंक, नियुक्ति प्रकार, क्षेत्र के आधार पर गिरावट और देखे गए रुझानों सहित महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) कानूनी क्षेत्र और न्यायिक सेवाओं में, विशेषकर भर्ती, प्रतिधारण और पदोन्नति की परिपाटियों के संबंध में महिलाओं के विरुद्ध प्रणालीगत भेदभाव को दूर करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे नीतिगत उपायों और पहलों का ब्यौरा क्या है ?

### उत्तर

#### विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : न्यायिक व्यवसाय और न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़े, जिनमें रैंक, नियुक्ति प्रकार, क्षेत्र और पिछले दस वर्षों के रुझान शामिल हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल और विभिन्न स्तरों पर न्यायपालिका जैसे प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा रखे जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष 2014 से अब तक उच्चतम न्यायालय में 06 महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों में 162 महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तारीख 18.03.2025 तक, उच्चतम न्यायालय में 02 महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों में 110 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। तारीख 28.02.2025 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 7,852 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियाँ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है, जो मलिक मज़हर सुल्तान मामले में

जनवरी 2007 के अपने आदेश के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करती है।

**(ख) :** विधिक क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध व्यवस्थित भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने से संबंधित नीतिगत उपाय और पहल, विशेष रूप से भर्ती, प्रतिधारण और पदोन्नति के संबंध में, न्यायपालिका और बार काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालाँकि, इन संस्थानों द्वारा लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने और विधिक क्षेत्र में महिलाओं का समर्थन करने के लिए कई पहल की गई हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने महिला वकीलों की सहायता के लिए विशेष सुविधाएँ लागू की हैं। उच्चतम न्यायालय विशेष रूप से महिला वकीलों के लिए समर्पित शौचालय, प्रतीक्षा क्षेत्र और लाउंज प्रदान करता है।
- न्यायालय परिसर के भीतर एक क्रेच (चाइल्डकेयर सेंटर) की स्थापना एक उल्लेखनीय सुविधा है, जो छोटे बच्चों के साथ महिला अधिवक्ताओं की सहायता के लिए है, साथ ही न्यायालय परिसर के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय भी हैं।
- इसी तरह, देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने महिला अधिवक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से सुविधाएँ शुरू की हैं। कुछ उच्च न्यायालयों में अलग-अलग महिला बार एसोसिएशन या समितियाँ हैं जो लिंग-विशिष्ट चिंताओं पर केंद्रित हैं, साथ ही महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष शौचालय, लाउंज और चेंजिंग रूम भी हैं।
- इसके अतिरिक्त, कई उच्च न्यायालयों ने बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति के माध्यम से सुरक्षा में सुधार किया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ महिला अधिवक्ता अक्सर आती हैं। न्यायालय, न्यायिक व्यवसाय में महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों और कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लिंग-संवेदनशीलता कार्यक्रम और कार्यशालाएँ भी आयोजित करते हैं।
- विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का प्रशासन करता है। इस अधिनियम में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं हैं, क्योंकि कानून के तहत सभी वर्गों के अधिवक्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है। हालाँकि, कई राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने महिला अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता सहित सहायता देने के लिए योजनाएँ शुरू की हैं।
- इसके अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने राज्य बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बार काउंसिल की विभिन्न अनुशासनात्मक और अन्य समितियों में कम से कम 25% सदस्य महिलाएं हों। इस निर्देश का उद्देश्य कानूनी बिरादरी के भीतर प्रमुख निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, समानता और विविधता को बढ़ावा देना है।

\*\*\*\*\*